initiated measures to revamp the Public Distributon System (PDS) to improve the reach of PDS commodities in identified areas. The Central Government in consultation with the State Governments and U.T. Admnistrations, identified about 1700 blocks which are covered by various area specific programmes such as Drought Prone Areas Programmes, Desert Development Programmes, Integrated Tribal Development Projects and certain Designated Hill Areas. The State Governments have been requested to initiate steps to ensure del'very of PDS commodities at Fair Price Shops in these identified areas. They propose to open about 11000 Fair Price Shops, issue ration cards to people who have not been provided one so far. The estimated population likely be served by this scheme is around 167 millions.

As a part of the scheme State Governments/UT. Administrations have been requested to eliminate bogus ration cards and set up village level Vigilance Committees *vo* monitor the distribution of PDS commodities at the FPSs. Additional commodities such as puleses, tea, soaps and iodised salt are also proposed to be distributed using the PDS outlets, whaerever necessary.

छापों के दौरान गेहूं तथा चावल के अपार भंडार का बरामद किया जाना।

443. श्री हरेन्द्र सिंह ईसपाल :
डा० जी० विजय मोहन रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में हाल ही में मारे गये छापों के दौरान गेहूं तथा चावल के अपार भंडार बरामद किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जमाखोरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या इस तरह के छापे दिल्ली से बाहर भी मारे जायेंगे?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) हाल ही में दिल्ली प्रशासन के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा 18 व्यापारियों के परिसरों की जांच के दौरान चावल की 2,91,857 क्विंटल मात्रा बरामद की गई है। दो चावल विक्रेताओं के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस ने खाद्यान्न व्यापारियों के परिसरों/उचित दर दुकानों/मिट्टी के तेल के डिपुओं और खाद्यान्न ले जाने वाले वाहनों के संबंध में 46 जांच कार्यवाहियां भी की जिसके परिणामस्वरूप फरवरी, 92 के पहले पखवाड़े में 8 मामलों में प्रथम रिपोर्टें दर्ज कराई गई है ।

(ग) राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और इसी तरह के कानूनों के उपबंधों के तहत आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और अन्य कदाचारों में लिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं ।

Price rise after the presentation of the Budget

444. SHRI GURUDAS DAS GUPTA :
SHRI CHATURNAN MISHRA :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether wholesale prices of many items rose after the presentation of budget for 1991-92.;

(b) if so, the reaons therefor ; and

(c) the steps taken by the Government to contain the price rise ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI G. VENKAT SWAMY) : (a) After the presentation of Budget for 1991-92 in July, 91 the wolesale prices of essential commodities, such as cereals, pulses dry chillies, coking coal, petrol, kerosene, atta, sugar, salt, Vanaspati, and mustard oil have shown a rising trend. The price indices of other items of mass consumption have either remained steady or declined during this period.

(b) In addition to the continuing impact of the inflationary tendency erupted in the economy during the later part of 1990-91, the increase in the prices of cereals like wheat and rise was caused due to revision in the procurement prices and consequent rise in issue prices, the gap in the demand and supply of edible oils and pulses, increase in railway freight rates during 1991, increase of excise duties on certain commodities, the unavoidable increase m petroleum product/prices (except for kerosene and diesel) and issue prices of sugar and fertilizers in the Budget for 1991-92,, fail in the production of khariff crops etc.

(c) Cabinet Committee on Prices under the Chairmanship of the Finance Minister regularly monitors the prices and supply position of various essential commodities, Import of edible oils against exim scrips through STC ^as been allowed. States have also been allowed to import edib'e oiis with foreign exchange earned by them. Public Distribution System (PDS) has been revamped and the PDS allocations of sugar, rice and wheat to certain States have been enhanced and upper limits have been imposed on exports of rice and wheat. States have directed to ensure strict enforcement of the Essential Commodities Act for dehoarding commodities in short supply and to take appropriate steps to ensure timelly and adequate supplies of essential commodities in all areas within the State and removing infrastructural constrains, if any The prices of 10 essentail commodities are being monitored on daily basis by the Ministry of Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मजबूत बनाया जाना

445. डा० अबरार अहमद :
चौधरी हरि सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) क्या प्रधान मंत्री के हाल ही के राजस्थान दौरे से इस प्रक्रिया में तेजी आयी है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने अभिज्ञात क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं पहुंचाने के कार्य में सुधार लाने के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नया रूप देने क लिये कदम उठाये हैं। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों जैसे सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, मरूस्थल विकास कार्यक्रम, समेकित आदिवासी विकास परियोजना और कुछ निर्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों के तहत आने वाले लगभग 1700 ब्लाकों की पहचान की गई है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे अतिरिक्त उचित दर की दुकानें खोलें उन लोगों को राशन कार्ड जारी करें, जिन्हें अब तक ऐसे राशन कार्ड जारी नहीं किये गये हैं, उचित दर दुकानों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिये कदम उठायें, जाली राशन कार्डों/यूनिटों को समाप्त